



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 122]

नई दिल्ली, बुधवार, 2 जुलाई, 1980/आषाढ़ 11, 1902

No. 122]

NEW DELHI, WEDNESDAY, 2 JULY, 1980/ASADHA 11, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना संख्या-24 आईटीसी (पीएन)/80

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 1980

आयात व्यापार नियंत्रण

विषय —जापान की सरकार द्वारा प्रदान की गई 1979-80 के लिए
जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के आयातों
के लिए आयात लाइसेंस जारी करने के लिए शर्तें

निसिद संख्या-आईटीसी/23/3/80 —1979-80 के लिए जापान
की सरकार द्वारा प्रदान की गई जापानी अनुदान सहायता येन 2 69
बिलियन (येन 2 687,563,000) के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के आयातों
के लिए आयात लाइसेंस जारी करने के लिए शामिल होने वाली नियम तथा
शर्तें जो इस सार्व० सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं जानकारी के
लिए अधिसूचित की जाती हैं।

सार्वजनिक सूचना सं० 24-आईटीसी (पीएन)/80, दिनांक 2-7-80 का
परिशिष्ट

जापान की सरकार द्वारा प्रदान किए गए 1979-80 के लिए 2 69
बिलियन (येन 2,687,563,000) के जापानी अनुदान सहायता
के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के आयातों के सम्बन्ध में लाइसेंस शर्तें

खण्ड-1—सामान्य शर्तें

1(1) जापान की सरकार द्वारा प्रदान की गई 2 69 बिलियन
जापानी अनुदान सहायता प्रो० ई० सी० एफ० और विकासशील देशों

के हक में संगठित की गई हैं। तदनुसार, इस ऋण के अधीन अधिप्राप्त
की जाने वाली पण्य वस्तुएं और उनसे सम्बन्धित प्रासंगिक सेवाएं जापान
और अनुबन्ध-1 की सूची में उद्धृत सभी देशों से आयात की जा सकती
हैं। ये देश इस ऋण के अन्तर्गत पात्र स्रोत देश होंगे। इस अनुदान
सहायता के अधीन जो पात्र मदे आयात की जा सकती हैं उनकी सूची
अनुबन्ध-2 में दी गई है।

1(2) लाइसेंस पर एक शीर्षक "1979-80 के लिए 2 69
बिलियन जापानी अनुदान सहायता होगा।" प्रथम और द्वितीय प्रत्यय
के लिए लाइसेंस संकेत "एस/जे० एन" होगा। ये प्रत्यय मुख्य नियंत्रक,
आयात निर्यात के आयात लाइसेंस के अधेष्टित पत्र में भी दुहराए जाएंगे।

1(3) बैंक खाते, जिनका प्रेषण सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम
से किया जा सकता है, के अतिरिक्त विशेषी मुद्रा के किसी भी प्रेषण
की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी। भारतीय अधिकारों
के बर्तीकरण के प्रति कोई भी भुगतान अधिकारियों को भारतीय रुपए में
चुकाना चाहिए। लेकिन ऐसे भुगतान लाइसेंस सूच्य के ही भाग होंगे
और इसलिए लाइसेंस पर ही प्रभावित किए जाएंगे।

1(4) आयात लाइसेंस लागत-सीमा-मात्रा के आधार पर 12 महीनों
की प्रारम्भिक वैध अवधि के साथ जारी किया जाएगा। लाइसेंस की
वैधता में वृद्धि के लिए लाइसेंसधारी को सम्बन्धित लाइसेंस प्राधिकारी से
सम्पर्क करना चाहिए जो इस मामले में आर्थिक कार्य विभाग (जापान
अनुभाग) से परामर्श करेगा।

1(5) पहले प्रादेश अनुबन्ध-1 में उल्लिखित जापान या अन्य पात्र देशों में स्थित विदेशी संभरकों को लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर या लागत और भाड़ा के आधार पर लिए जाने चाहिए और वे (आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीनों की अवधि के भीतर) आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेज दिए जाने चाहिए। "पहले प्रादेशों" का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा लिए गए उन कृष्य प्रादेशों या कृष्य संविदाओं में है जो भारतीय लाइसेंसधारी से प्राप्त प्रादेश की पुष्टि करने के बाद विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् समर्थित हों या भारतीय आयातक और विदेशी अभिकर्ताओं के प्रादेश/और या ऐसे भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण प्रादेश स्वीकरणीय नहीं है।

1(6) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण वस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, जापान अनुभाग को नहीं पहुंचे जाते हैं। यदि उपर्युक्त पैरा 1(5) में यथा उल्लिखित पहले प्रादेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर प्रादेश क्यों नहीं दिए जा सके इन कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस को सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए। प्रादेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा। वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 4 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसे लाइसेंसधारी को प्रेषित करेंगे।

पोत लदान के लिए आखिरी तिथि निर्दिष्ट करने में हम बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 31-3-1981 के बाद की न हो।

खण्ड-2—संभरण ठेके का समझौता करते समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें

2(1) (क) ठेके का मूल्य येन या यू० एम० डालर या पौण्ड स्टर्लिंग में एक येन, एक सेट या एक पेनी से कम की भिन्न के बिना ही अभिव्यक्त होना चाहिए और इसमें भारतीय अभिकर्ता का कमीशन, प्रादि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रूप में चुकाया जाएगा। भारतीय रूप या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। जहाज पर्यटन निःशुल्क लागत-बीमा और भाड़ा धनराशि अलग-अलग प्रदर्शित की जा सकती है परन्तु ठेके में बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भाड़े का खर्चा वास्तविक आधार पर देय होगा या ठेके में निविष्ट किए गए भाड़े का खर्च वास्तविक खर्चों के अनिवार्य देय धनराशि होगी।

(ख) संविदा में नकद आधार पर अर्थात् बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो को जापानी संभरकों द्वारा पोतलदान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए।

(ग) कृष्य प्रादेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण प्रादेश केवल अंग्रेजी में होने चाहिए।

2(2) आयात लाइसेंस के मद्दे केवल एक संविदा की जानी चाहिए। विशेष मामलों में एक से अधिक संविदा की प्रविष्टि की अनुमति दी जा सकती है जिनके लिए वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग से आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि के तत्काल बाद पूर्व अनुमोदन ले लेना चाहिए।

2(3) संभरक की पात्रता :

संभरक पात्र खोन देशों का राष्ट्रिक होगा या पात्र खोन देशों में पंजीकृत और समाविष्ट न्यायिक व्यक्ति होगा।

खण्ड-3—संभरण ठेकों में निम्नलिखित बातें विशेष रूप से समाविष्ट होनी चाहिए

3(1) 1979-80 के लिए, 2.69 बिलियन ~~रुपये~~ अनुदान सहायता से सम्बद्ध इस संविदा की व्यवस्था 18 मार्च, 1980 को भारत और जापान की सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार की गई है।

3(2) विदेशी संभरकों को भुगतान उस ~~प्रकार~~ के लिए प्राधिकार-पत्र" (ए/पी) के माध्यम से किया जाएगा जो 1979-80 के लिए जापानी अनुदान सहायता के अधीन बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो के नाम में सहायता एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, पालियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 द्वारा और जारी किया जाएगा।

3(3) विदेशी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक और भारत सरकार द्वारा और हमरी और जापान सरकार द्वारा अपेक्षित हो।

3(4) उस मामले में जिसमें संभरक जापान में स्थित हो और भारतीय दूतावास, टोकियो के परामर्श से पातलदान की व्यवस्था करने को तैयार है और इसके लिए सम्बन्धित मान की सुपुर्दगी के कार्यक्रम को भारतीय दूतावास टोकियो को सूचना देगा और अपेक्षित पात परिवहन के लिए 4 मास पहले ही भारतीय दूतावास टोकियो का अधिसूचित करवाएगा जिसमें उचित व्यवस्था की जाए। विशेष मामलों में, जहां भारतीय आयातक यह चाहता हो तो अधिसूचना की अवधि कम की जा सकती है। आवश्यक होने देते हुए प्रत्येक पोतलदान के साथ जापानी संभरक को आयातक का केवल सूचना भेजने के लिए भी सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो का भेजी जानी चाहिए।

3(5) नीचे संकेतिक प्रपत्र में विदेशी संभरकों से एक प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए अथवा यह संविदा में दर्शाया जाना चाहिए :—

"मैं (हम) एतद्द्वारा यह स्पष्ट करता (करते) हैं कि मेरी (हमारी) कम्पनी (पात्र खोन देश) में पंजीकृत है और पात्र खोन देशों के राष्ट्रिकों द्वारा निर्दिष्ट है या पात्र खोन देशों में पंजीकृत और शामिल हुए न्यायिक व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित है।"

खण्ड-4—भारत सरकार द्वारा ठेके का अनुमोदन

4(1) जैसे ही प्रादेशों का अन्तिम रूप दे दिए जाते हैं, लाइसेंसधारी को दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियां या समुद्रपार संभरकों को भारतीय आयातक द्वारा दिए गए कृष्य प्रादेश के साथ समुद्रपार संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण प्रादेश की चार प्रतियां या सभी प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियों के साथ अनुबन्ध-3 के प्रपत्र में "ए/पी जारी करने के आवेदन" की 2 प्रतियां सहित सगल वैध आयात लाइसेंस की 2 फोटो प्रतियां अवर सचिव (टी) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए। उपर्युक्त प्रक्रिया संविदा की विषयवस्तु या उसकी कोमत के आवश्यक आर्गोथनों से उत्पन्न सभी संविदा मर्गोथनों के लिए भी लागू होगी।

4(2) यदि ठेके के दस्तावेज "ए/पी जारी करने के लिए आवेदन-पत्र" और अन्य सम्बन्धित दस्तावेज सही जाएं जाएंगे तो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) जापान अनुभाग ठेके का अनुमोदन करेगा और उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेज के एक सेट की सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक और भारत के राजदूतावास टोकियो को भेजने की व्यवस्था करेगा।

4(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित दस्तावेज की प्राप्ति के बाद सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, पालियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 बैंक ऑफ इण्डिया,

टोकियो के लिए अनुबन्ध-4 के रूप में विदेशी संभरकों का भुगतान करने के लिए "भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी)" जारी करेगा। ए/पी की प्रतियां भारत के राजदूतावास टोकियो, आयातक, भारत में आयातक के बैंक और जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय की पृष्ठांकित की जाएंगी।

4(4) भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की प्राप्ति के बाद बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो जापान की सरकार, भारत के राजदूतावास टोकियो, भारत के बैंक के आयातक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को सूचना देने हुए इस प्राप्ति की सूचना से संभरक का अवगण कराएगा।

4(5) पोलवदान प्रभावी करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकरो के माध्यम से ए/पी में उल्लिखित दस्तावेज बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो दस्तावेज में उल्लिखित धनराशि को विदेशी संभरक का उसके बैंकरो के माध्यम से रिहा करेगा।

4(6) संभरक के लिए ए/पी जारी करने के लिए और भुगतान की व्यवस्था करने के लिए बैंक ऑफ इण्डिया टोकियो का वेध बैंक खर्च भारत में आयातक के सम्बद्ध बैंक द्वारा बैंक ऑफ इण्डिया टोकियो का प्रेषण द्वारा सामान्य बैंक प्रणाली से भारत सरकार के वेधे का प्रभावित किए बिना ही निर्धारित किए जाएंगे।

खण्ड-5. रुपया जमा करने का उत्तरदायित्व

5(1) मूल विनियम पोल परिवहन दस्तावेज साथ ही साथ बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो द्वारा भारत में आयातक के सम्बद्ध बैंक को भेजे जाएंगे और भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (जो अनुबन्ध-3 के-ए में उल्लिखित है) की शाखा द्वारा उस बैंक को दस्तावेजों के विनियम में केवल इस बात का सुनिश्चय करने के बाद ही सम्बद्ध आयातक को देने चाहिए कि विदेशी संभरक को चुकाई गई येन/यू.एस. डालर/पीपुल स्टैबिलिटी धनराशि के बराबर रुपया उन मामलों में जहाँ पर देने योग्य है व्याज के खर्च सहित संभरक को भुगतान कर दिया है और उस धनराशि पर विदेशी संभरक को बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो द्वारा भुगतान की तिथि से आन्तरिक रुपया जमा करने की तिथि तक ही की अवधि पर पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से और शेष अवधि के लिए 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से हिमाज लगाकर व्याज सार्वजनिक सूचना सं० 46-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 16-6-76 के अनुसार सरकारी लेखा में जमा कर दिया गया है। व्याज दोनों दिना, अर्थात् जिस दिन विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है, और जिस दिन सरकारी लेख में रुपया जमा किया जाता है, के लिए देय है। देखिए सार्वजनिक सूचना सं० 103-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 12-10-76 द्वारा आशोधित सार्वजनिक सूचना सं० 74-आईटीसी (पीएन)/74 दिनांक 31-5-74 भुगतानों की येन/यू.एस. डालर/पीपुल धनराशि के बराबर रुपया की गणना करने के लिए अपनार्इ जाने वाली विनियम टर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना सं० 8-आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 17-1-76 में निर्धारित मुद्रा विनिमय की मिश्रित दर द्वारा। या वह दर होगी जो कि मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनियम नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए। इस सम्बन्ध में कोई भी परिवर्तन जब और जैसे हो आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा। इस बात का सुनिश्चय करने का उत्तरदायित्व सम्बद्ध भारतीय बैंक का होगा कि आयात दस्तावेज आयातकों को सौंपने से पहले ही वेध धनराशि सरकारी लेख में सही रूप से जमा कर दी गई है। तदनुसार ही को भी यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि अपने बैंकरो में दस्तावेज लेने से पहले ही वेध धनराशि लेख में सही रूप से जमा कर दी गई है। जिस लेखा गीर्ष में उपर्युक्त रुपया जमा करना चाहिए वह "के डिपॉजिट्स एण्ड एडवांसज 843 मिश्रित डिपॉजिट्स—डिपॉजिट्स

फार परचेजिंग एट एक्स्ट्रा एक्साइ परचेजिंग/परचेस ग्रान्ट ऐंड फ्राम गवर्नमेंट ऑफ जापान फार 1979-80 (येन 2.69 बिलियन ग्रान्ट ऐंड डेबिट रिमीफ)।

5(2) उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, तीस हजार। दिल्ली में सरकार की साख में नकद जमा होनी चाहिए। या यदि वह सुविधाजनक न हो तो स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की किसी शाखा या इसके उपसंगी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (हुण्डीकर्ता) में प्राप्त एक हुण्डी (डिमाण्ड ड्राफ्ट) के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, तीस हजार की शाखा, दिल्ली-6 (हुण्डी ग्राहक और प्रापक) की सार्वजनिक सूचना सं० 184-आईटीसी (पीएन)/68, दिनांक 30-8-68, सं० 233-आईटीसी (पीएन)/68, दिनांक 4-10-68, सं० 132-आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 5-10-71, सं० 74-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 और सं० 103-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित सरकारी लेख में जमा करने के लिए धन प्रेषण करना चाहिए।

5(3) सरकार द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद मात्र दिनों के भीतर सम्बद्ध भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से वह अनिवार्य धनराशि सेवा खर्चों के निमित्त भेजेगा जो भारत सरकार द्वारा मांगी जाए। बालान के विभिन्न कालखंडों की भरते समय आयातकों/उनके बैंकरो को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं० 103-आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 12-10-76 के साथ पढ़ी जाने वाली सार्वजनिक सूचना सं० 132-आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 5-10-71 के पैरा 2 में निर्धारित सूचना और सार्वजनिक सूचना सं० 74-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 में भी निर्धारित सूचना बालान के कालखंड "धन परेषण और, प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण व्योरे" में निरपवाद रूप से निरूपित किए गए हैं। खजाना बालान में निम्न-लिखित व्योरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए:—

- (क) वित्त मंत्रालय के भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र सं० और दिनांक।
- (ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके सम्बन्ध में अपनार्इ गई परिवर्तन की दर के साथ निरूपित किए जाने है।
- (ग) विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि।
- (घ) चुकाए गए व्याज की धनराशि और वह अवधि जिसके लिए यह गिना गया है।
- (ङ) जमा की गई कुल धनराशि

(व्याज की गणना विदेशी संभरक को भुगतान की तिथि से सरकारी लेख में समस्त रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए की जानी है)।

उसके पश्चात् सी० ए० ए० एंड ए० द्वारा जारी किए गए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र का सर्वश्रेष्ठ देते हुए और बीजक तथा पोल परिवहन दस्तावेजों को संभरक करते हुए खजाना बालान रुपया जमा करने का साध्य देने हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी० ए० ए० एंड ए० को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी:—भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चय करना चाहिए कि रुपए का निक्षेप बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो से आयातकों की सूचना और अपरिवर्तनीय पोलवदान दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सी० ए० ए० एंड ए० फिर मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा।

5(4) भारत में सम्बद्ध बैंक ऑफ इण्डिया, को लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति पर हपया निक्षेपों को धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित "एम" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया को भेजना चाहिए।

खण्ड-6. विविध शर्तें

6(1) आयात लाइसेंस के उपयोग की रिपोर्ट :- भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी होने के बाद आयातक को पोन लवानों और उनके अधीन किए गए भुगतानों के सम्बन्ध में और जो पोनलवान होने बाकी हैं उनके विषय में एक मासिक रिपोर्ट सी० ए० ए० एंड ए० प्राधिकार कार्य विभाग जिस मंत्रालय, यू० सी० प्रो० बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

6(2) संभरकों का विशेष शर्तें अधिसूचित करना :- लाइसेंसधारी को चाहिए कि वे आयात लाइसेंस की उन विशेष शर्तों से संभरक की प्रवगत करावें जो समझौते का पालन करने में संभरकों पर प्रभाव डाल सकती हैं।

6(3) विवाद :- यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच यदि कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो द्वारा भुगतानों से पूर्व संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें माफ-साफ "भुगतान के निगम" के अधीन अनुबन्ध-1 में दर्शाई जानी चाहिए। विवादों से निपटने की शर्तें ठेके की शर्तों में शामिल होनी चाहिए।

6(4) भविष्य अनुदेश :- आयात लाइसेंस या उसके सम्बन्ध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों से सम्बन्धित जापान से 1979-80 के लिए अनुदान सहायता के अधीन सभी आभारों को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए निवेशों या अनुदेशों या आवेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा।

6(5) अतिक्रमण या उल्लंघन :- उपयुक्त खण्डों में स्थिर की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

6(6) अनुबन्धों की सूची :-

अनुबन्ध 1--पात्र स्त्रोत देशों की सूची

अनुबन्ध 2--पात्र पण्य वस्तुओं की सूची

अनुबन्ध 3--भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन करने का प्रपत्र

अनुबन्ध 4--भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) का प्रपत्र

अनुबन्ध-1

[सदर्थ खण्ड 1 कांडिका 1(5)]

पात्र स्त्रोत देशों की सूची

(क) प्रो ई सी डी देश

ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रिया

बेल्जियम

कनाडा

डेनमार्क

फिनलैंड

फ्रांस

जर्मनी संघीय गणराज्य

यूनान

ग्राइसलैंड

इटली

जापान

आयरलैंड

लक्समबर्ग

नीदरलैंड

न्यूजीलैंड

नार्वे

स्वीडन

स्विटजरलैंड

तुर्की

यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य

(ख) बिकातशील देश तथा उसके क्षेत्र

(ख-1) नाम--प्रो० ए० ई० सी० बिकातशील देश

1. अफ्रीका, उत्तरी सहारा

मिश्र

मोरोको

तुनीशिया

2. अफ्रीका, दक्षिणी सहारा

अंगोला

बोत्सवाना

बरन्डी

केमेरून

केप वर्डी द्वीप समूह

केन्द्रीय अफ्रीकन गणतन्त्र

चाद

कमोरो द्वीप समूह

इथोपिया

जाम्बिया

कांगो, वमोह गणराज्य

इन्वेबीरियल गार्डना

षाना

गिनी

ग्राइबरी कोस्ट

कीनिया

लेसोथो

लाइबीरिया

मानागासी गणतन्त्र

मलावी

माली

मारितेनिया

मारीशस

मोजाम्बीक

नाइजर

पुर्तगाली गिनी

रियूनियन

रोडेसिया

रवान्डा

सेंट केलिना और डेस (2)

साओटोम प्रिन्साइड

सेनेगाल

सेजिलिय

सियरा लिओन

सोमालिया

सूडान

स्वाजीलैंड

टेरो अफर्स और इत्साम

टोंगा

युगान्डा

तैजानिया गणतन्त्र सभ
अपर बोन्टा
जाम्बरे गणतन्त्र
जाम्बिया

3. अमेरिका उत्तरी ओर केन्द्रीय

बेहमन
बारबाडोस
बेलाइज
बरमुडा
कोस्टारिका
क्यूबा
डोमिनिकन गणतन्त्र
एल साल्वेडोर
गुवाटेमाला
ग्वाटेमाला
हेती
हॉन्डुरस
जेमैका
मार्टिनिक्
मैक्सिको
नीदरलैंड एंटीलीज
निकारागुवा
पनामा

- (1) पहले स्पेनी गिनी का प्रवेश, परनेडी पी द्वीप समूह
(2) निम्नलिखित द्वीपों सहित :—
असेन्शन, ट्रिस्टन डा क्वेन्ससेन्सिस्थ, नाइटिंगेल गफ।
(3) मुख्य द्वीप समूह, अरूबा, बोनाहरे क्युराकाओ साहा,
सेन्ट मार्टिन (दक्षिण भाग)
सेन्ट पियरी और मिकेलोन
ट्रिनिडाड और टोबैगो
वेस्ट इण्डिज (शाखा) एन०आई०ई०
(क) सम्बन्धित राज्य (1)
(ख) आश्रित (2)

4. दक्षिणी अमेरिका

अर्जेन्टीना
बोलिविया
ब्राजील
चिली
कोलम्बिया
फास्कलैड द्वीप समूह
फ्रांसिसी गिनी
गुयाना
पाराग्वे
पीरू
सूरिनाम
उरुग्वे

5. मध्य पूर्वी एशिया

बेहरीन
इजराइल
जॉर्डन
नेबनान
ओमन
सिरिआई अरब गणतन्त्र

यूनाइटेड अरब एमिरात
यमन अरब गणतन्त्र (3)
यमन जनवादी डी०आर० (4)

6. दक्षिणी एशिया

अफगानिस्तान
बांग्लादेश
भूटान
बर्मा
मालदीव
नेपाल
पाकिस्तान
श्रीलंका

7. सुदूर पूर्वी एशिया

बुर्नेई
होंगकांग
खमेर गणतन्त्र
कोरिया गणतन्त्र
लाओस
मकाओ
मलेशिया
फिलिपाइन
मिंगापुर
नाइवान
थाइलैंड
तिमोर
वियतनाम गणतन्त्र
वियतनाम जनवादी गणतन्त्र

8. ओसिनिया

कोक द्वीप समूह
फिजी
गल्बर्ट और इलाइस द्वीप
फ्रांसिसी पोलिनेशिया (5)
नीर
न्यूकोलेडोनिया
न्यूहेसिस (त्रि और प्र)
हिडू
पैसिफिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य) (6)
पापुवा न्यू गिनी
सोलामन द्वीप समूह (त्रि)
टोंगो
वालिस और फुतुना
पश्चिमी समाओ

9. यूरोप

साइप्रस
जिब्राल्टर
ग्रीक
माल्टा
स्पेन
तुर्की
यूगोस्लाविया

(ख-2) ओ०पी०ई

अल्जीरिया
बोर्नियो
लीबियाई अरब गणतन्त्र
सेबान

नाइजीरिया
इक्वेटोर
वेन्जुएला
ईरान
इराक
कुवैत
कातार
मउदी अरब
आबु धाबी
इन्डोनेशिया

- (1) मुख्य द्वीप : एन्टिगुवा, बोमिनिका, ग्रेनेडा, सेंट किट्स (सेन्ट क्रिस्टोफी) नेविल ग्रुएला, सेंट लुसिया और सेंट विसेन्ट ।
- (2) मुख्य द्वीप : मोल्तेरन, सेमान, तुर्क और काइकाम और ब्रिटिश और जिन द्वीप समूह ।
- (3) प्रजमान, डूबन, कुजाइरड, राग अर पैरा, गारजाह और उम अल क़ैवेन ।
- (4) अदन और विभिन्न पुर्तगा जल प्रान्त सहित ।
- (5) सोमयटी द्वीप समूह (ताहिती सहित) को शामिल करने हुए, आन्दुल द्वीप समूह, दुओमोट, जाम्बियर ग्रुप और माकेयन द्वीप समूह ।
- (6) पैसिफिक द्वीप समूह का ट्रस्ट प्रदेश : कागोलीन द्वीप समूह, मांजोन द्वीप समूह और सेरिना द्वीप समूह (गाम का आइलर) ।

अनुसूच 2

पात्र पर सूची

1. गोल्ल
2. विशेष इस्पात और मिश्रधातु इस्पात नहिन इस्पात
3. टूकों और ट्रेक्टरों के विनिर्माण के लिए संयंत्र, मशीन और पुर्जे
4. रसायन
5. भारत-जापान संयुक्त उद्यम के लिए फालतू पुर्जे, संघटक और कच्चा माल
6. बिजली के हर्षों के लिए संघटक, संयोजक और फालतू पुर्जे
7. मशीनरी, संघटक, संयोजक, फालतू पुर्जे और कच्चा माल
8. भारत के राष्ट्रीय मधु उद्योग निगम के लिए मशीनरी और उपस्कर
9. बम्बई हाई और गोर डिप्लेपमेन्ट प्रोजेक्ट के लिए, मशीनरी और उपस्कर
10. उर्वरक और ऐसी अन्य मवे जिन पर आपन से सहमति हो ।

अनुसूच 3

“भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र जारी करने के लिये प्रायता पत्र”

संख्या दिनांक
सेवा में,

महायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मन्त्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
यु०सी०प्रो० बैंक बिल्डिंग, प्रथम मजिल,
पार्लियामेन्ट स्ट्राट, नई दिल्ली-110001 ।

विषय :—1979-80 के लिये 2.69 बिलियन जापानी अनुदान महायता
येन के अधीन जापान से आयात ।

महायत,

आर उल्लिखित अनुदान महायता के अधीन जापान
से जापान आयात के सम्बन्ध में

है सम्बद्ध सम्भरक के नाम से बैंक आफ इण्डिया,
टोकियो के लिए भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र जारी करने के लिए
हम आपको निम्नलिखित व्योरे प्रस्तुत करते हैं :—

- (क) भारतीय आयातक का नाम और पता
- (ख) आयात लाइसेंस की सं०, दिनांक और मूल्य और वह तारीख
जिस तक वैध है ।
- (ग) प्राप्ति के तरीके—क्या यह सीधे क्रय या औद्योगिक खुले
अन्तर्राष्ट्रीय निविदा पर प्राप्ति है । इसके मायने में यदि
कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेतित होना चाहिए
कि क्या सविदा का निर्णय उपयुक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव
के आधार पर किया गया है ।
- (घ) माल का संक्षिप्त विवरण
- (ङ) माल का उद्गम देश
- (च) सविदा का कुल लागत भाड़ा मूल्य (येन में) ।
- (छ) यदि कोई हो तो भारतीय रुपये में भुगतान की जाने वाली
भारतीय एजेंट के कमीशन की प्रतिशत ।
- (ज) वह कुल लागत तथा भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए
भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता है ।
- (झ) सम्भरकों के साथ की गई सविदा की संख्या और दिनांक ।
- (झ) सम्भरक का नाम और पता और पात्र प्रमाण पत्र भी भेजे ।
(दो प्रतियां में) ।
- (ट) वे भुगतान शर्तें और सम्भावित निधि जिनका सविदा के
अन्तर्गत भुगतान देय होंगे ।
- (ठ) सुपुर्दगी को पूर्ण करने को प्रत्याशित तिथि ।
- (ड) भारतीय बैंक टांकियों को भुगतान करते समय दिये जाने वाले
दस्तावेज (प्रत्येक सेट का मध्या और निपटान का संकेत
करें) प्रत्येक सेटों की सं० और उनका निपटान दिखाने हुए ।
- (व) पोतलदान अनुवेश (बाह्यमानरण/पोर्ट-शिपमेन्ट) की अनुमति
दी गई है या नहीं निश्चित कीजिए ।
- (त) भारत से आयातक के बैंक का नाम और पता
- (थ) क्या उम्मी लाइसेंस के अन्तर्गत सविदा (सविदापत्र) कर दी
गई है । यदि हा तो ऐसी सविदा की दिनांक और मूल्य ।

भवदीय

अनुसूच 4

संख्या

भारत सरकार

वित्त मन्त्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में,

बैंक आफ इण्डिया,
टोकियो शाखा,
टांकियों (जापान) ।

विषय :—2.69 बिलियन के लिए जापानी अनुदान महायता के
अधीन आयात भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना ।

प्रिय महोदय,

1 आपके बैंक के साथ 13-3-79 को किए गए समझौते की शर्तों
के अनुसार आपका एनद्वारा यथा संलग्न व्योरे (जो परिशिष्ट में दर्शाए
गए हैं) के अनुसार सर्वश्री
के नाम से येन अन्तर्गत
के भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।

2. रुपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (पीएन) की पात्रता के बारे में सम्भरकों की सूचना दे और इसकी एक प्रति जापान सरकार, आयातक बैंक, भारत के राजतुतावास, टोकियो और हम मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाए।

3. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र को शर्तों के अनुसार भुगतान परिशिष्ट में यथा संकेतित नदान दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

4. आयातक द्वारा आपका दस्तावेजों को भेजने आदि के लिए भाड़ी सहित या किये जाने वाले बैंकिंग भाड़े टोकियो में भारतीय तूतावास/आयातक के बैंक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

5. जैसे ही सम्भरक द्वारा प्रस्तुत किए गए नदान दस्तावेजों के आधार पर आपके द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है तो इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में मंत्रालय और आयातक के बैंक को भेजी जानी चाहिए।

6. हम मंत्रालय की विशेष अनुमति के बिना भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र के लिए कोई भी संशोधन जारी नहीं किया जा सकता है।

7. यह भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र तक वैध रहेगा।

भवदीय,

लेखा अधिकारी

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :—

1. आयातक को उनके पत्र सख्या दिनांक के मन्दर्भ में।

2. आयातक का बैंक उसमें निवेदन किया जाता है कि भारतीय बैंक आफ इण्डिया, टोकियो ब्रांच से दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी सम्भरकों को येन/यू.एस. डालर/पीड के बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करें। विदेशी सम्भरकों को भुकाई गई धनराशि के बराबर रुपय की गणना सार्वजनिक सूचना संख्या 8-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए के अनुसार विदेशी सम्भरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रस्तावित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी। विदेशी सम्भरक को भुगतान करने की तिथि से सरकार के लेख में मुख्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना सं. 46-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 16-6-76 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक दर पर और इससे अधिक की गणना की गई अवधि के लिए 15 प्रतिशत की दर से व्याज भी सरकारी लेख में जमा करना होगा। व्याज दोनों दिनों के लिए दिया जाएगा अर्थात् वह तिथि जिसको विदेशी सम्भरक को भुगतान किया जाता है और वह तिथि भी जिसको सरकारी लेख में रुपया निवेदन किया जाता है। (इस दर में यदि कोई परिवर्तन किया गया हो तो तुरन्त उसकी सूचना दी जाएगी)। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमा शुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल सेट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जानी है।

ये धनराशियां या तो रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी, दिल्ली में जमा करनी चाहिए या स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी शाखा या इसकी अनुपयी संस्थाओं या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 (आदेशित और आयात) के नाम में और उसको वेब वर्णनी टूण्ड्री के माध्यम से करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना संख्या 233-आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 24-10-68, संख्या 132 आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71, संख्या 74 आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 31-5-74 और संख्या 103 आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-76

की शर्तों की ओर दिलाया जाता है। लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह "के डिपोजिट्स एण्ड एडवाइज 843 मित्रिय डिपोजिट्स—डिपोजिट्स फार परचेजिस एटसेकट्रा एन्नाड—परचेजिस ग्रान्ट ऐड फ्राम दि गवर्नमेंट आफ जापान फार 1979-80 (येन 2.69 बिलियन ग्रान्ट ऐड डेबिट रिलीफ)"।

जिन मामलों में मुख्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इण्डिया तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना सं. 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-1971 के अनुसार नकद जमा लिया जाता है उनमें व्याज की सूक्ष्म रूप में एक प्रतिनिधि बैंक आफ इण्डिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणों का पूर्ण विवरण देने हुए भ्रष्टेपण-पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी :—

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग),

पहली मंजिल, यू.सी.ओ. बैंक बिल्डिंग,

समद मार्ग, नई दिल्ली।

जिस मामले में मुख्य रुपया ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित दर्शनी टूण्ड्री द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिये। सभी मामलों में व्याज की भुकाई गई धनराशि और जिस अवधि के लिए व्याज की गणना की गई है उसके साथ जमा किए गए मुख्य रुपय का पूरा क्वीर हम विभाग को भेजना चाहिए।

समूहवार सम्भरक के बैंक के खर्चों सहित यदि कोई हो तो, बैंकिंग खर्च और बैंक आफ इण्डिया, टोकियो ब्रांच के अन्य खर्च इण्डियन बैंक आफ इण्डिया, टोकियो शाखा द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे।

4. भारतीय तूतावास, टोकियो।

5. अवसर सचिव (टी.ए.) शाखा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।

लेखा अधिकारी

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक,
आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE (Department of Commerce)

Public Notice No. 24-ITC(PN)/80

New Delhi, the 2nd July, 1980

IMPORT TRADE CONTROL

Subject: Licensing conditions in respect of public sector imports under the Japanese Grant Aid of Yen 2.69 Billions for 1979-80.

No IPC/23/3/80.—The terms and conditions governing the issuance of import licences to the public sector undertakings under the Japanese Grant Aid of Yen 2.69 Billion (Yen 2,687,563,000) for 1979-80 as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

Appendix to Ministry of Commerce Public Notice No. 24-ITC(PN)/80 dated the 2nd July, 1980

Licensing Conditions in respect of Public Notice Sector imports under the Japanese Grant Aid of Yen 2.69 Billion

(Yen 2,687,563,000/-) for 1979-80 extended by the Government of Japan

Section I—General Conditions :

(i) The Japanese Grant Aid of Yen 2.69 billion extended by the Government of Japan is untied in favour of OECD and developing countries. Accordingly the commodities and services incidental thereto to be procured under this Grant Aid can be imported from Japan and all countries enumerated

in the list at Annexure-I which will be the eligible source countries under this Grant. The list of eligible commodities that can be imported under this Grant Aid is at Annexure-II.

I(ii) The licence will bear the superscription "Yen 2.69 billion Japanese Grant Aid for 1979-80". The licence code for the first and second suffix will be "S/JN". These will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence.

I(iii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank charges which may be remitted through normal banking channels. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments however, will form part of the licence value and will, therefore be charged to the licence.

I(iv) The import licence will be issued on CIF basis with an initial validity of 12 months. For extension of the validity of the licence, the licensee should approach the licensing authority concerned who shall consult the Department of Economic Affairs (Japan Section) in the matter.

I(v) Firm order must be placed on C&F basis on the overseas suppliers located in Japan and in other eligible countries mentioned in Annexure-I and sent to the Under Secretary, Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi, (within 4 months from the date of issue of the import licence). "Firm Orders" means purchase orders placed by the Indian licensees on the Overseas supplier duly supported by order confirmation by the latter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of Overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I(vi) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Japan Section, within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para I(V) above cannot be placed within 4 months for valid reasons, the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within 4 months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If however, extension is sought beyond 4 months from the date of issue of this import licence, such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licensee.

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-3-1981.

Section II—Special points to be kept in view while negotiating a supply contract :

II(i)(a) The C&F value of the contract should be expressed in Yen or US Dollar or Pound Sterling without fraction less than one Yen, one Cent or one Penny and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees. In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupee or in any other currency. The FOB cost and freight amount may be shown separately but it should be clarified in the contract whether the freight charges will be payable on actual basis or whether the freight charges indicated in the contract would be the amount payable irrespective of the actual charges.

(b) The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents by the Japanese Suppliers to the Bank of India, Tokyo.

(c) The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II(ii) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases more than one contract may be permitted to be entered into for which prior approval of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance,

should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II(iii) Eligibility of Supplier

The supplier shall be a national of the eligible source countries, or a juridical person registered and incorporated in the eligible source countries.

Section III

The following provision should be specifically incorporated in the supply contract :—

III(i) The contract is arranged in accordance with the Agreement dated the 18th March, 1980 between the Governments of India and Japan concerning the grant Aid of Yen 2.69 billion for 1979-80 "and will be subject to the approval of Government of India".

III(ii) Payments to the overseas suppliers shall be made through an 'Authorisation to pay (A/P)' which will be issued by the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 in favour of the Bank of India, Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1979-80.

III(iii) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan on the other.

III(iv) Where Suppliers are located in Japan, they agree to make shipping arrangement in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose they would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India, atleast four weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases, where the importers require this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

III(v) A certificate in the form indicated below—

"I (we) hereby state that my (our) Company has been registered in _____ (eligible source country) and is governed by nationals of the eligible source countries or juridical persons registered and incorporated in the eligible source countries."

should be obtained from the overseas supplier or it should be got incorporated in the contract itself.

Section IV—Contract Approval by Government of India :

IV(i) As soon as the orders are finalised, the licensee should forward to the Under Secretary (T.), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi 4 copies of the contract duly signed by both parties or purchase orders by the Indian importer placed on the overseas supplier supported by order confirmation in writing by the overseas supplier or their photo copies complete in all respects together with two photo copies of the relevant valid import licence as also two copies of the "Request for issue of A/P" in the form at Annex. III. The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

IV(ii) If the contract documents "Request for issue of A/P" and other connected documents are found to be in order the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Japan Section will approve the contract and will arrange to send one set of the documents mentioned in (i) above each to the CAA&A and the Embassy of India, Tokyo.

IV(iii) On receipt of the documents mentioned at (ii) above the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 will issue an 'Authorisation to Pay' (A/P) to the Bank of India, Tokyo in the form at Annexure IV for making payment to the overseas supplier. Copies of the A/P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo, the importer, importer's Bank in India and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

IV(iv) On receipt of the Authorisation to Pay (A/P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of this receipt to the supplier under intimation to the Government of Japan Embassy of India, Tokyo, the importers' bank in India and the CAA&A.

IV(v) The foreign supplier shall, after affecting shipment present through his bankers the documents specified in the A/P to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the Supplier through his bankers.

IV(vi) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for advising the A/P and for arranging payment to the overseas supplier shall be settled by the concerned importer's Bank in India by remittances to the Bank of India, Tokyo through normal banking channel without affecting the Government of India's account.

Section V—Responsibility for rupee deposit :

V(i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned importer's bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised Banks as mentioned in (O) in Annexure III who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen, US Dollar/Pound sterling Payments made to the supplier along with interest charges thereon in cases where payable calculated at the rate of 9 per cent per annum for the first thirty days and at 15 per cent for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the foreign Supplier to the date of actual rupee deposit, is deposited into Government of India account in terms of the Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-76. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the supplier and also the day on which rupee deposits is made into Government account vide Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen/US \$/£. Payment will be the prevailing composite rate of exchange as laid down in CCT&E Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCT&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The licensee should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances-843-Civil Deposits-Deposits for purchases etc., abroad-purchase Grant Aid from the Government of Japan" for 1979-80 (Yen 2.69 billion Grand Aid-Debt-relief).

V(ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi, or if this is not possible it should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and Payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-8-1968, No. 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-68 and No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976.

V(iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 and also in Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 read with Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following

particulars should invariably be furnished in the treasury Challans :

- (a) Ministry of Finance 'A/P' (Authorisation to Pay) No. and date.
- (b) Amount of Yen Currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.
- (c) Date of payment to the foreign supplier.
- (d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.
- (e) Total amount deposited.

(Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the supplier upto and inclusive of the date of deposit of rupee equivalents into Government Account).

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the A/P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

Note.—Importer's Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

V(iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Section VI—Miscellaneous provisions :

VI(i) Reports on the utilisation of the import licence :

The importer should send a monthly report, after the A/P has been issued regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VI(ii) Notifying Suppliers of Special Conditions:

The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VI(iii) Disputes :

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the licensee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure I under "Terms of Payment". Provision dealing with a settlement of disputes be included in the condition of contract.

VI(iv) Future Instructions :

The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Grant Aid for 1979-80 from Japan.

VI(v) Breach or violation :

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control Act).

VI(vi) List of Annexures :

Annexure I—List of eligible source countries.

Annexure II—List of eligible commodities.

Annexure III—Form of Request for issue of Authorisation to Pay (A/P).

Annexure IV—Form of letter of Authorisation to Pay (A/P)

ANNEXURE I

{Ref. Section I—Para 1(v)}

List of Eligible Source Countries

A. OECD Countries

Australia
Austria
Belgium
Canada
Denmark
Finland
France
The Federal Republic of Germany
Greece
Iceland
Ireland
Italy
Japan
Luxembourg
the Netherlands
New Zealand
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
the United Kingdom and
the United States .

B. Developing Countries & Territories

(b) Non-O.P.E.C. Developing countries

I. Africa North of Sahara

Egypt
Morocco
Tunisia

II. Africa, South of Sahara

Angola
Botswana
Burundi
Cameroon
Cape Verde Islands
Central African Rep.
Chad
Comoro Islands
Congo, People's Republic of Dahomey (1)
Equatorial Guinea
Ethiopia
Gambia
Ghana
Guinea
Ivory Coast
Kenya
Lesotho
Liberia
Malagasy Republic
Malawi
Mali
Mauritania
Mauritius
Mozambique
Niger
Portuguese Guinea
Reunion
Rhodesia
Rwanda
St. Helena and Dep (2)
Sao Tome and Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swaziland
Terra. Afars and Issas
Togo
Uganda
Un. Rep. of Tanzania
Upper Volta

Zaire Republic
Zambia

- (1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernando Po.
- (2) Including the following island : Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gough.
- (3) Main islands, Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, St. Eustacit St. Martin (Southern Part).

III. America, North and Cent.

Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
El Salvador
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Netherlands Antilles
Nicaragua
Panama
St. Pierre & Miquelon
Trinidad and Tobago
West Indies (Br.) n.e.e.

(a) Associated States (1)

(b) Dependencies (2)

IV. America, South

Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Falkland Islands
French Guyana
Guyana
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay

V. Asia, Middle East

Bahrain
Israel
Jordan
Lebanon
Oman
Syrian Arab Republic
United Arab Emirates (3)
Yemen Arab Republic
Yemen, People's D.R. (4)

VI. Asia, South

Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Burma
Maldives
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

VII. Asia, Far East

Borneo
Hong Kong
Khmer Republic
Korea, Republic of Laos
Macao
Malaysia
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Timor
Vietnam Rep. of
Viet-Nam Dem Rep.

- (1) Main islands : Antigua, Dominica, Grenada, St. Kitts (St. Caristephe), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent.
- (2) Main islands; Montserrat, Gayman, Turks and Caicos, and British Virgin Islands.
- (3) Ajman, Dubai, Fujairah, Ras-al Khaimah, Sharjah and Umm-al Quaiwain.
- (4) Including Aden and Various sultanates and emirates.
- (5) Comprising the Society Islands (including Tahiti.) The Austral Islands, the Tuamotu-Gambier Group and the Marquesas Islands.
- (6) Trust Territory of the Pacific Islands, Caroline Islands, Marshall Islands, and Marine Islands (except Guam).

VIII. Oceania

Cock Islands
Fiji
Gilbert & Ellice Is.
French Polynesia (5)
Nauru
New Caledonia
New Hebrides (Br. and Fr.)
Hieu
Pacific Islands (US) (6)
Papua New Guinea
Solomon Islands (Br.)
Tongo
Wallis and Futuna
Western Samoa

IX Europe

Cyprus
Gibraltar
Greece
Malta
Spain
Turkey
Yugoslavia

(b2) Member or Associate Countries of OPEC

Algeria
Bolivia
Libyan Arab Republic
Gabon
Ecuador
Venezuela
Iran
Iraq
Kuwait
Qatar
Saudi Arabia
Abu Dhabi
Indonesia
Nigeria

ANNEXURE II**Eligible Commodity List**

1. Rolls
2. Steel including special steel & alloy steel.
3. Components, attachments and spares for manufacture of trucks and tractors.
4. Chemicals.
5. Spares, components and raw materials for Indo-Japanese Joint Ventures.
6. Components, attachments and spares for power tillers.
7. Machinery, components, attachments, spares and raw materials.
8. Machinery and equipment for the National Small Industries Corporation of India.
9. Machinery and equipment for the Bombay High Offshore Development Project.
10. Fertilizer and such other items as may be mutually agreed upon.

ANNEXURE III**"Request for Issue of the Authorisation to Pay"**

NO.

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street,
New Delhi-110001.

Subject :—Import from Japan under the Japanese Grant Aid of Yen 2.6 billion for 1979-80.

Sir,

In connection with the Import from Japan under the above mentioned Grant Aid, we furnish the following particulars to payable you to issue the A/P to the Bank of India, Tokyo in favour of the Supplier concerned :—

- (a) Name and Address of the Indian Importer.
- (b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.
- (c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or Formal open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.
- (d) Brief description of the goods.
- (e) Origin of the goods.
- (f) Gross C&F value of contract (in Yen).
- (g) Amount of Indian agents' commission (in Yen), if any, payable in Indian rupees.
- (h) Net C&F value (in Yen) for which the A/P is required.
- (i) Name and date of the contract with Suppliers.
- (j) Name and Address of the supplier and attach an eligibility certificate (in duplicate).
- (k) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.
- (l) Expected date of completion of deliveries.
- (m) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).
- (n) Shipment instructions (indicate if transshipment/part-shipment permitted or not permitted).
- (o) Name and Address of the Importer's Bank in India.
- (p) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and if so, the No. date and value of such contract.

Yours faithfully,

ANNEXURE IV

No.

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE**

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the.....

To

The Bank of India,
Tokyo Branch
Tokyo(Japan)

Sub :—Import under Japanese Grant Aid for Yen 2.6 billion Issue of Authorisation to pay.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 13.3.1979 entered into with your Bank, you are hereby authorised to pay an amount not exceeding Yen _____ to M/s. _____ (as per details given in the Appendix).

2. Please advise the Suppliers of the fact of receipt of this authorisation to Pay (A/P) and endorse a copy of this advice to the Government of Japan, Importers, Bank, Embassy of India, Tokyo and this Ministry.

3. Payments to the suppliers in terms of the A/P will be made on the basis of shipping documents etc. as indicated in the Appendix.

4. The banking charges including charges for handling documents payable to you by the importer will be settled by the Embassy of India Tokyo/Importers Bank.

5. As and when any payment is made by you on the basis of shipping documents etc. presented by the supplier, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry and the importer's bank.

6. No amendments to A/P may be issued in the absence of a specific authority from this Ministry.

7. The A/P will remain valid upto _____.

Yours faithfully,
Accounts Officer.

Copy forwarded to :—

1. Importer _____ with reference to their letter No. _____ dated _____.

2. Importer's Banker _____ they are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen/US \$/£ payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupees equivalent of amount disbursed to the overseas suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to Overseas Suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC (PN)/76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @ 9 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 15 per cent per annum for the period excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Government Accounts is required to be deposited into the Government of India account in terms of Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-1976. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the overseas supplier and also the date on which rupee deposit is made into Government account. (Any change in this rate will be intimated if and when made). It should be ensured that these deposits are made before the original set of

import documents are handed over to the importer for Customs Clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a Demand Draft obtained by them from any Branch of the S.B.I. or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the S.B.I., Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968, No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-74 and 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The head of Account to be credited is 'K-Deposits & Advances-843-CIVIL Deposit for purchases etc. abroad Purchases under Grant Aid from the Government of Japan for 1979-80—(Yen 2.6 billion Grant Aid-Debt Relief).

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

The banking charges, of the Bank of India, Tokyo Branch, including charges of the overseas suppliers bankers, if any, should be settled directly between the Indian Bank and the Bank of India, Tokyo Branch.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary (TA) Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

Accounts Officer,

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of Imports and Exports.